Drishti IAS

करेंट अफेयर्स हरियाणा

सितम्बर (संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा **3**

- मंत्रिपरिषद ने हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड कंपनी के गठन को दी हरी झंडी 3
- सरचार्ज माफी योजना-2022 4
- पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग (ए) को मिलेगा आरक्षण 4
- 'हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016' में संशोधन को मंत्रिमंडल की स्वीकृति 5
- गेहूँ की 22 नई प्रजातियाँ देश को समर्पित 6
- बदमाशों व अवैध गतिविधियों के खिलाफ चला 'ऑपरेशन आक्रमण-2' 7
- नई स्कूल स्वास्थ्य योजना 'सेहत' का शुभारंभ 7
- 'ई-रूपी वाउचर' के माध्यम से कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का वितरण 8
- कृषि एवं उद्यान विभाग बीएससी, एमएससी व पीएचडी छात्रों को देगा इंटर्नशिप 8
- हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी-2022 9
- हरियाणा की ऐतिहासिक नगरी 'राखीगढ़ी' को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान 9
- हरियाणा में शुरू होगी 'ई-बुक्स योजना', 'सुषमा स्वराज स्मृति सम्मान' भी होगी शुरू 10
- अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं और सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों को सौर ऊर्जा पर मिलेगी क्रमश: 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत सब्सिडी 11
- फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का विश्वस्तरीय स्टेशन की तर्ज़ पर होगा पुनर्विकास 11
- एचएयू के कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार 12
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सफल बनाने में हरियाणा की नई पहल 12
- हरियाणा एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी-2022 का प्रारूप तैयार 12
- हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला आईडीए एजुकेशन अवार्ड-2022 13
- ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) 13
- अंबाला से श्रीनगर और लखनऊ की हवाई यात्रा जल्द 14
- डॉ. सोनिया खुल्लर होंगी हरियाणा की नई स्वास्थ्य महानिदेशक 15
- हरियाणा-सस्केचेवान गोलमेज सम्मेलन 15
- अंबाला ज़िले के बड़ौला में स्थित सरकारी स्कूल का नाम होगा शहीद करनैल सिंह या उनकी पत्नी के नाम पर 16
- चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम हुआ शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 16
- गुरुग्राम और नूंह में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क 17
- हरियाणा राज्य में पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्डचेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ 17

नोट :

हरियाणा

मंत्रिपरिषद ने हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड कंपनी के गठन को दी हरी झंडी

चर्चा में क्यों ?

31 अगस्त, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार के अधीन हवाई अड्डे/हवाई पट्टियों/हेलीपैडों के विकास कार्यों के साथ-साथ भारत सरकार के अधीन एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने जैसी अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिये हरियाणा विमानपत्तन विकास निगम लिमिटेड कंपनी के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा, नागरिक उड्डयन विभाग और राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से 'अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर' परियोजना पर कार्य करेंगे।
- हरियाणा के हिसार और अन्य हवाई क्षेत्रों में एकीकृत विमानन हब की स्थापना एवं संचालन के उद्देश्य से उपरोक्त निगम की स्थापना के प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य राज्य सरकार की हवाईअड्डा परियोजनाओं/संयुक्त उद्यम परियोजनाओं का प्रबंधन, विनियमन और कार्यान्वयन करना है। इसके अलावा, निगम हवाई अड्डों के संचालन, रखरखाव, विकास, डिज़ाइन, निर्माण, उन्नयन, आधुनिकीकरण और प्रबंधन में सहायता करेगा।
- निगम सभी संपत्तियों और बुनियादी ढाँचे, जैसे- रनवे, टैक्सी-वे, एप्रन, यात्रियों के लिये टर्मिनल, कार्गो सुविधाओं के प्रावधान सहित हवाई अड्डों के नवीनीकरण, वैमानिकी गतिविधियों और सेवाओं को प्रदान करने के लिये भवन विस्तार एवं प्रबंधन हेतु भूमि की खरीद/भूमि अधिग्रहण में सहायता करेगा।
- साथ ही निगम हिसार में समेकित एविएशन हब और अन्य हवाई क्षेत्रों/हवाई अड्डों पर निगम परियोजना के विकास, परियोजना वित्तपोषण, परियोजना निगरानी, स्थापना, सुदृढ़ीकरण, उन्नयन, मरम्मत, पुनर्वास, सुधार, संचालन, निर्माण, रखरखाव और कार्यान्वयन में निर्माण, डिज़ाइन, संरचना विकसित करने में या तो सीधे या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में कार्य करेगा।
- इसके अलावा, हरियाणा विमानपत्तन विकास निगम लिमिटेड का निगमन परियोजनाओं और बुनियादी ढाँचे के प्रावधान तथा विकास के लिये वाणिज्यिक प्रारूप पर योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों, रियायतों और अन्य संविदात्मक व्यवस्थाओं की खरीद, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव में सहायता करेगा।
- इसके अतिरिक्त, निगम नागरिक उड्डयन विभाग के परियोजना स्थल, भूमि और निर्मित क्षेत्रों की योजना, विकास, संचालन और रखरखाव तथा निपटान का कार्य निर्धारित कानूनों, विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप भी करेगा।
- उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ 7 जुलाई, 2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार की 'अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर' योजना के अंतर्गत महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के शहर की तरफ के क्षेत्र में समेकित विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने के प्रस्ताव पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण के लिये लगभग 1605 एकड़ भूमि पहले ही चिह्नित की जा चुकी है।
- समेकित विनिर्माण क्लस्टर परियोजना हरियाणा के नागरिक उडन्यन विभाग तथा भारत सरकार द्वारा स्वायत्त निकाय के रूप में शुरू की गई राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में क्रियान्वित की जाएगी।

नोट :

सरचार्ज माफी योजना-2022

चर्चा में क्यों ?

31 अगस्त, 2022 को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा बिजली के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिये सरचार्ज माफी योजना-2022 शुरू की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का लाभ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनका बिल 31 दिसंबर, 2021 तक बकाया था तथा अब तक भी बिल बकाया है। यह योजना Connected and Disconnected दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिये है।
- डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत घरेलू (शहरी तथा ग्रामीण) कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा तथा उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का भुगतान करना होगा।
- उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त अथवा अगले तीन बिलों के साथ भी जमा करवा सकता है। एकमुश्त जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।
- उन्होंने बताया कि फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशि एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में जमा नहीं करवाता और आगामी 6 बिल लगातार जमा नहीं करवाता तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के उपभोक्ता उठा सकते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की बकाया मूल राशि पर लगने वाले सरचार्ज की पुनर्गणना की जाएगी व वर्तमान ब्याज की दर 5 प्रतिशत मासिक की बजाय साधारण 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
- सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के बने गलत बिल विभाग की शर्तों के अनुसार ठीक किये जाएंगे। ऐसे उपभोक्ता, जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है, वो भी इस योजना को अपना सकते हैं। बशर्ते उनको अपना केस न्यायालय से वापस लेना पड़ेगा।
- इस योजना का लाभ उठाने का अवसर राज्य के लगभग 2240985 उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनमें 24479 सरकारी उपभोक्ता भी शामिल हैं तथा विभाग का लगभग 1834 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया जा सकता है। यह योजना 30 नवंबर, 2022 तक जारी रहेगी।

पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग (ए) को मिलेगा आरक्षण

चर्चा में क्यों ?

31 अगस्त, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग (ए) के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये इस संबंध में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व जज, न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) दर्शन सिंह के नेतृत्व में गठित आयोग ने पिछड़े वर्गों के नागरिकों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिये गहन जाँच की। आयोग ने पाया कि पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए (बीसी-ए) के लोगों को राजनीतिक सेटअप में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण उन्हें पंचायती राज संस्थानों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

- आयोग द्वारा ग्राम पंचायत में अनुशंसित आरक्षण
  - प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच के पदों को पिछड़ा वर्ग (ए) के लिये कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (क) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू 5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।

नोट :

- बशर्ते कि यदि पिछड़े वर्ग (ए) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का दो प्रतिशत या अधिक है तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग (ए) से संबंधित कम से कम एक पंच होगा।
- इसी प्रकार एक ब्लॉक में सरपंच के पदों की कुल संख्या का आठ प्रतिशत और यदि डेसिमल वैल्यू5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए पिछड़ा वर्ग (ए) के लिये आरक्षित किया जाएगा।

- आयोग द्वारा पंचायत समिति में अनुशंसित आरक्षण
  - प्रत्येक पंचायत समिति में सदस्य के पद पिछड़ा वर्ग (ए) के लिये कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किये जाएंगे, जो ब्लॉक की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (ए) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।
- आयोग द्वारा ज़िला परिषद में अनुशंसित आरक्षण
  - प्रत्येक ज़िला परिषद में सदस्य के पद पिछड़ा वर्ग (ए) के लिये कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे, जो ज़िला परिषद क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (ए) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी।
  - आयोग ने कहा है कि शीर्ष न्यायालय के निर्देशानुसार आरक्षण किसी भी पंचायती राज संस्थान में अनुसूचित जाति और बीसी (ए) के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
  - आगे स्पष्ट किया गया है कि पिछड़े वर्ग (ए) के लिये इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या को अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या के साथ जोड़ने पर यदि उनकी कुल संख्या पंचायती राज संस्थानों की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो पिछड़े वर्ग (ए) के लिये आरक्षित सीटों की संख्या को वहीं तक रखा जाएगा, जिससे कि अनुसूचित जाति और बीसी (ए) का आरक्षण ग्राम पंचायत के पंच, पंचायत सीमित के सदस्य और ज़िला परिषद् के सदस्य की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।
  - आयोग द्वारा इन सिफारिशों को स्पष्ट करते हुए उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिये गाँव में पिछड़े वर्ग ब्लॉक ए की आबादी ग्राम सभा की कुल आबादी का 25 प्रतिशत है तो 5 प्रतिशत सीटें पिछड़ा वर्ग ब्लॉक (ए) के नागरिकों के लिये आरक्षित होंगी।
  - जहाँ किसी गाँव में अनुसूचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है तो पिछड़े वर्ग (ए) को अपनी आबादी की प्रतिशतता के बावजूद भी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा।

'हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016' में संशोधन को मंत्रिमंडल की स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

1 सितंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016' में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार ने हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 और संबंधित नियमों को अधिनियमित किया है, ताकि राज्य में एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र सृजित किया जा सके, जो कारोबार करने की सहूलियत से मेल खाता हो और साथ ही व्यवसाय करने में होने वाली देरी के साथ-साथ लागत को कम करने के लिये श्रेष्ठ वैश्विक मानकों से भी बेहतर हो।
- हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड (एचईपीबी) का गठन हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 की धारा 3 के तहत किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) का गठन किया गया है।
- अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समिति के अध्यक्ष हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव समिति के सदस्य-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।
- नगर एवं ग्राम आयोजना, पर्यावरण, वन, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), वित्त, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, बिजली, शहरी स्थानीय निकाय, श्रम, एचएसआईआईडीसी के महानिदेशक या उद्योग एवं वाणिज्य विभागों के प्रशासनिक सचिव समिति के निदेशक सदस्य हैं।

नोट :

- ईईसी की प्रमुख भूमिका सरकार की विभिन्न योजनाओं/नीतियों के तहत प्रोत्साहन/विशेष पैकेज के मामलों की जाँच करना और हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड को इसकी सिफारिश करना है।
- ईईसी आगे जीएसटी की प्रतिपूर्ति सहित विशेष पैकेज के लिये मामलों का अनुमोदन एवं सिफारिश करती है। हालाँकि, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रशासनिक सचिव इस समिति के सदस्य नहीं हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रशासनिक सचिव को अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति (ईईसी) के सदस्य के रूप में शामिल करने के लिये हरियाणा उद्यम संवर्धन नियम, 2016 के नियम 4 (1) में संशोधन की आवश्यकता थी।
- इसके अलावा मंत्रिमंडल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (कार्यों की सीमा) विनियम, 1973 में संशोधन के लिये एक्स-पोस्ट (घटनोत्तर) स्वीकृति प्रदान की। इस संशोधन के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बजाय एचपीएससी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ग्रुप-बी विभिन्न पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने हेतु अनिवार्य किया गया है। अन्य सभी ग्रुप-बी पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया एचपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है।

गेहूँ की 22 नई प्रजातियाँ देश को समर्पित

चर्चा में क्यों ?

1 सितंबर, 2022 को भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर) करनाल के निदेशक डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आईआईडब्ल्यूबीआर के पर्यवेक्षण में देश को गेहूँ की 22 नई प्रजातियाँ किसानों को समर्पित की गई।

प्रमुख बिंदु

- यह पहला मौका है, जब 2022 में एक साथ इतनी अधिक प्रजातियाँ देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की सहभागिता से अनुमोदित की गई हैं।
- इनमें पाँच प्रजातियाँ आईआईडब्ल्यूबीआर करनाल (हरियाणा) की हैं, इसके अलावा संस्थान की दो प्रजातियों का क्षेत्र विस्तार भी किया गया है। ये देश में गेहूँ उत्पादन में क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इससे देश के किसानों के सामने अधिक विकल्प मौजूद होंगे।
- भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान (आईआईडब्ल्यूबीआर) करनाल और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) के संयुक्त तत्त्वावधान ग्वालियर में 29 व 30 अगस्त को आयोजित 61वीं संगोष्ठी में ये निर्णय लिये गए थे।
- डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि संगोष्ठी में प्रजाति पहचान समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें समिति ने 27 प्रस्तावों पर चर्चा की। इसमें से 22 गेहूँ की प्रजातियों का अनुमोदन कर किसानों के खेतों के लिये अनुमोदित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इन्हें केंद्रीय प्रजाति अनुमोदन समिति द्वारा रिलीज किया जाएगा।
- गौरतलब है कि इन 22 प्रजातियों में पाँच प्रजातियाँ आईआईडब्ल्यूबीआर करनाल की हैं। जिसमें डीबीडब्ल्यू-370, डीबीडब्ल्यू-371, डीबीडब्ल्यू-372 और डीबीडब्ल्यू-316 के अलावा डीडीडब्ल्यू-55 शामिल हैं।
- जल्द बुवाई व अधिक उत्पादन वाली डीबीडब्ल्यू-370 का उत्पादन 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 371 का 75.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, दो जोन के लिये अनुमोदित की गई 372 का उत्पादन 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर (मध्य भारत के लिए 75.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर) के लिये अनुमोदित किया गया है।
- 316 का उत्पादन (देर से बुवाई वाली प्रजाति) पूर्वोत्तर भारत के लिये 41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तो सीमित पानी में सेंट्रल जोन के लिए कठिया गेहूँ की प्रजाति डीडीडब्ल्यू-55 को अनुमोदित किया गया है, इसमें सिर्फ एक पानी लगाना होता है।
- आईआईडब्ल्यूबीआर के प्रमुख अन्वेषक (फसल सुधार) डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि इसके अलावा आईआईडब्ल्यूबीआर की दो प्रजातियाँ डीबीडब्ल्यू-187 व 303 मेगा प्रजातियों में शामिल हो गई हैं। 187 ऐसी प्रजाति हैं, जिसे 20 मिलियन हेक्टेयर के लिये अनुमोदित किया है, जो देश में पाँच मिलियन हेक्टेयर रकबे तक पहुँच गई है। हरियाणा में 50 प्रतिशत ये प्रजाति बोई जा रही है।
- इन दोनों प्रजातियों का क्षेत्र विस्तार करते हुए मध्य क्षेत्र में उच्च उर्वरता, अगेती बुवाई के लिये अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो प्रजातियाँ अनुमोदित की गई हैं, उनमें पीबीडब्ल्यू 826 (दो जोन के लिये), पीबीडब्ल्यू 883, आईएआरआई नई दिल्ली की एचडी 3369, 3406, 3411 व 3467, आईआरआई इंदौर की एचआई 1653, 1654, 1650, 1655, 8826, एमएसीएस पुणे की 6768, 4100, सीजी बिलासपुर की 1036 आदि शामिल हैं। आईएआरआई नई दिल्ली की दस प्रजातियाँ शामिल हैं।

नोट :

बदमाशों व अवैध गतिविधियों के खिलाफ चला 'ऑपरेशन आक्रमण-2'

चर्चा में क्यों ?

6 सितंबर, 2022 को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा बदमाशों की धरपकड़ के लिये एक दिन का विशेष अभियान 'ऑपरेशन आक्रमण- 2' चलाया गया।

प्रमुख बिंदु

- 'ऑपरेशन आक्रमण- 2' अभियान के तहत पुलिस ने राज्यभर में दिनभर व्यापक छापेमारी करते हुए आईपीसी, एनडीपीएस, एक्साइज और आर्म्स एक्ट आदि की संबंधित धाराओं के तहत 710 केस दर्ज करके 964 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
- पुलिस महानिदेशक ने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा 5 सितंबर को चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य आपराधिक तत्त्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना, स्ट्रीट क्राइम व अवैध हथियारों पर अंकुश लगाना, अवैध शराब की धरपकड़ सहित मादक पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसना है।
- उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक ज़िले में बदमाशों व असामाजिक तत्त्वों के भागने की गुंज़ाइश छोड़े बिना उन पर नकेल कसने के लिये उनके इलाकों/सड़कों/घरों में अचानक रेड कर अपराधियों के अंदर कानून का भय पैदा करना चाहते हैं।
- विभिन्न ज़िलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार फील्ड में लगभग 3500 पुलिसकर्मियों की 645 टीमों ने कई स्थानों पर रेड की। छापेमारी के दौरान रेडिंग टीमों ने 45 उद्घोषित अपराधियों और 34 बेल जंपर्स को काबू करने में भी कामयाबी हासिल की। पकड़े गए ये बदमाश कई मामलों में वांछित थे और गिरफ्तारी से बचने के लिये फरार चल रहे थे।
- पानीपत ज़िले में सर्वाधिक 116 आरोपी गिरफ्तार हुए, वहीं गुरुग्राम में 108 और अंबाला में 102 को काबू किया गया। इसी प्रकार, सर्वाधिक 24 पीओ और बेल जंपर्स सोनीपत ज़िले में दबोचे और 9 को पानीपत से गिरफ्तार किया गया।
- डीजीपी ने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों, उपकरणों और अन्य वस्तुओं की जाँच के लिये प्रदेश के जेल परिसरों में भी छापेमारी की गई।
- विशेष अभियान का आकलन करते हुए उन्होंने इसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई और आम जनता के बीच कानून में विश्वास को और मज़बूती देने की दिशा में एक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह का विशेष अभियान जारी रहेगा।
- उल्लेखनीय है कि 'ऑपरेशन आक्रमण'आपराधिक व असामाजिक तत्त्वों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी करने का एक विशेष राज्यस्तरीय अभियान है। इसके तहत छापेमारी करने वाली पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस की ये टीमें आपराधिक तत्त्वों को फरार होने की गुंज़ाइश छोड़े बिना उन पर अंकुश लगाने हेतु संयुक्त रूप से कार्रवाई करती हैं।

नई स्कूल स्वास्थ्य योजना 'सेहत' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

5 सितंबर, 2022 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जाँच के लिये आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना 'सेहत' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2020 व 2021 के प्रदेश के 93 शिक्षकों को सम्मानित भी किया।
- राज्यपाल ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना 'सेहत'शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत आगामी शैक्षणिक सत्र से साल में दो बार 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। जाँच में एकत्रित किये गए डाटा को ई-उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी स्थान पर बच्चे का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होगा।

नोट :

- इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये अनेक कदम उठाए हैं। हरियाणा देश का ही नहीं, संभवत: विश्व का पहला प्रदेश है, जहाँ 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों और शिक्षकों को 5 लाख टैब नि:शुल्क प्रदान किये गए।

'ई-रूपी वाउचर' के माध्यम से कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का वितरण

चर्चा में क्यों ?

7 सितंबर, 2022 को हरियाणा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि विभाग द्वारा पहली बार 'ई-रूपी वाउचर'के माध्यम से कृषि उपकरणों पर सब्सिडी का वितरण किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में उन्होंने बताया कि इस नई पहल के लागू होने के बाद जहाँ एक तरफ किसानों को अपनी सब्सिडी पाने के लिये दर-दर नहीं भटकना होगा, वहीं दूसरी तरफ इस डिजिटल मोड के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन में और अधिक पारदर्शिता आएगी।
- उन्होंने बताया कि ज़िलास्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा चयनित होने के बाद किसान संबंधित उपकरणों की लागत के संबंध में विभाग द्वारा अनुमोदित निर्माताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं और खरीद के समय ही उनको अनुदान राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
- डॉ. मिश्रा ने बताया कि अब किसानों को अपनी जेब से पूरी राशि का भुगतान नहीं करना होगा, क्योंकि ई-रूपी पहल के बाद किसानों को लागत का केवल अपना हिस्सा ही देना होगा। इस प्रकार किसानों को जो पहले कुल लागत की व्यवस्था के लिये ब्याज का वहन करना पड़ता था, उस अतिरिक्त बोझ से राहत मिलेगी।

कृषि एवं उद्यान विभाग बीएससी, एमएससी व पीएचडी छात्रों को देगा इंटर्नशिप

चर्चा में क्यों ?

7 सितंबर, 2022 को हरियाणा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि राज्य का कृषि एवं उद्यान विभाग अब बीएससी, एमएससी और पीएचडी छात्रों को इंटर्नशिप देगा। इस इंटर्नशिप के लिये छात्रों को विभाग द्वारा स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मेरिट के आधार पर प्रत्येक विभाग में बीएससी के लिये 10, एमएससी एवं पीएचडी के लिये 5-5 छात्रों का इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिये चयन किया जाएगा और विभिन्न डिविजनों में कार्य दिया जाएगा। इंटर्नशिप पूरी होने पर छात्रों को प्रमाण-पत्र भी दिये जाएंगे।
- डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि इस योजना के तहत हिसार के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय एवं हरियाणा में स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट, हरियाणा के सभी छात्रों को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एवं बागवानी विभाग में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा।
- इसके तहत कृषि एवं बागवानी विभाग के क्षेत्र में बीएससी, एमएससी और पीएचडी डिग्री के छात्रों को पारस्परिक लाभ के लिये शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप के दौरान विभागीय कार्यक्रमों, कार्यप्रणाली, तकनीक केंद्रों, किसानों से मिलने का अवसर एवं उनसे बातचीत और कृषि एवं बागवानी फसलों के तकनीकी ज्ञान की जानकारी जानने का अवसर प्राप्त होगा।
- डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि विभाग से प्राप्त इंटर्नशिप का यह अनुभव छात्रों के भविष्य में काफी मददगार साबित होगा। यह इंटर्नशिप न तो कोई नौकरी है और न ही विभागों में नौकरी के लिये ऐसा कोई आश्वासन है।
- इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत बीएससी छात्रों की इंटर्नशिप 4 सप्ताह की रहेगी, जबकि कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में एमएससी और पीएचडी के छात्रों के लिये इंटर्नशिप कार्यक्रम 8 से 12 सप्ताह का होगा।
- बीएससी के वे छात्र, जिनको विश्वविद्यालय द्वारा पहले ही 13,000 रुपए प्रतिमाह का स्टाईपेंड दिया जा रहा है, उनको केवल विभागों में काम के लिये इंटर्नशिप प्रोग्राम की सुविधा दी जाएगी। जबकि एमएससी छात्रों को 9,000 रुपए एवं पीएचडी छात्रों को स्टाइपेंड के रूप में 12,000 रुपए कृषि व बागवानी विभाग द्वारा दिये जाएंगे।

नोट :

हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी-2022

चर्चा में क्यों ?

9 सितंबर, 2022 को हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 'हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी-2022' की अधिसूचना जारी की।

प्रमुख बिंदु

- शहरीकरण और औद्योगीकरण के लिये अब हरियाणा में किसानों की ज़मीनों का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। किसानों की इच्छा के आधार पर ही ज़मीन खरीदी जाएगी।
- इसके साथ ही अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिये प्रदेश में लैंड बैंक तैयार किया जाएगा, ताकि परियोजनाओं को समय पर ज़मीन मिल सके और विकास कार्य जल्दी हो सके।
- किसानों की इच्छा से ज़मीन मिलने के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) प्रकाशित विकास योजना में शहरी क्षेत्र के भीतर स्थित आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत और बुनियादी ढाँचे का विकास करेगा।
- इसके अलावा, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) भी हरियाणा में नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करेगा। भू-मालिकों को भूमि अधिकार प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
- गौरतलब है कि 29 जुलाई को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी-2022 को मंज़ूरी दी गई थी।
- नीति के तहत कोई भी भूमि मालिक सीधे या एग्रीगेटर के माध्यम से आवेदन मांगने के 60 दिनों के भीतर परियोजना के लिये भूमि की पेशकश कर सकेगा। इस अवधि को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है, जो 30 दिनों से अधिक नहीं होगी। आवेदन के लिये कोई शुल्क नहीं होगा और आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा।
- भू-मालिक भूमि के बदले विकसित भूमि भी ले सकते हैं। यह परियोजना की कुल लागत में भूमि मालिकों की दी गई अविकसित भूमि के बाज़ार मूल्य पर आधारित होगी।
- विकास परियोजना के लिये योगदान करने वाले प्रत्येक भू-मालिक को वार्षिक अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसे परियोजना की कुल लागत में शामिल किया जाएगा। यदि एग्रीगेटर के माध्यम से भूमि की पेशकश की जाती है तो एग्रीगेटर पारिश्रमिक प्राप्त करने का पात्र होगा, बशर्ते कि पारिश्रमिक 0.5 प्रतिशत से कम न हो।

हरियाणा की ऐतिहासिक नगरी 'राखीगढ़ी' को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान

चर्चा में क्यों ?

10 सितंबर, 2022 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राखीगढ़ी में निर्माणाधीन म्यूजियम भवन में इस क्षेत्र को पुरातत्त्व स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को निर्देश दिये कि राखीगढ़ी में संरक्षित साइट की खुदाई के कार्य को तेज़ गति से पूरा किया जाए। साथ ही, इन ऐतिहासिक साइट्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई व्यक्ति इन साइट्स को नुकसान न पहुँचा पाए।
- सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक नगर 'राखीगढ़ी'को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिये सरकार द्वारा राखीगढ़ी में म्यूजियम का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 हज़ार वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सहेज कर रखा जाएगा।
- राखीगढ़ी के पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित होने से एक ओर जहाँ पर्यटन बढ़ेगा, वहीं हरियाणा के राजस्व में भी वृद्धि होगी और यहाँ पर्यटकों के आने से गाँव के युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे।
- राखीगढ़ी में बन रहे इस म्यूजियम में फोटोग्राफ्स लैब्स तैयार की गई है, जिसमें चित्रों के माध्यम से आगंतुक राखीगढ़ी के इतिहास को जान सकेंगे। इसके अलावा, म्यूजियम में किड्स ज़ोन भी बनाया गया है। पहली बार हरियाणा में किसी म्यूजियम में किड्स ज़ोन का निर्माण करवाया गया है, ताकि बच्चे भी खेल-खेल में अपने इतिहास से अवगत हो सकें।

नोट :

- इसके अलावा ओपन एयर थिएटर, गैलरी, पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया गया है, जिससे आगंतुक, विशेषतौर पर युवा पीढ़ी को इतिहास की जानकारी मिलेगी।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में पर्यटन स्थलों व पाँच ऐतिहासिक स्थल बनाने के लिये 2500 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, उनमें राखीगढ़ी भी शामिल है। प्रदेश सरकार भी यहाँ 32 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक संग्रहालय बना रही है। इसमें रेस्ट हाउस, हॉस्टल और एक कैफे का निर्माण किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार ज़िले के नारनौंद उपमंडल में स्थित है। यहाँ राखीखास और राखीशाहपुर गाँवों के अलावा आसपास के खेतों में पुरातात्त्विक साक्ष्य फैले हुए हैं। राखीगढ़ी में सात टीले (आरजीआर-1 से लेकर आरजीआर-7) हैं। ये मिलकर बस्ती बनाते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इस गाँव में पहली बार 1963 में खुदाई शुरू की थी। इसके बाद 1998-2001 के बीच डॉ. अमरेंद्रनाथ के नेतृत्व में एएसआई ने फिर खुदाई शुरू की। बाद में पुणे के डेक्कन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. वसंत शिंदे के नेतृत्व में 2013 से 2016 व 2022 में राखीगढ़ी में उत्खनन कार्य हुआ।
- राखीगढ़ी में 1998 से लेकर अब तक 56 कंकाल मिले हैं। इनमें 36 की खोज प्रो. शिंदे ने की थी। टीला संख्या-7 की खुदाई में मिले दो महिलाओं के कंकाल करीब 7,000 साल पुराने हैं। दोनों कंकालों के हाथ में खोल (शैल) की चूड़ियाँ, एक तांबे का दर्पण और अर्ध कीमती पत्थरों के मनके भी मिले हैं। खोल की चूड़ियों की मौजूदगी से यह संभावना जताई जा रही है कि राखीगढ़ी के लोगों के दूरदराज के स्थानों के साथ व्यापारिक संबंध थे।
- प्रो. शिंदे के अनुसार राखीगढ़ी में पाई गई सभ्यता करीब 5000-5500 ई.पू. की है, जबकि मोहनजोदड़ो में पाई गई सभ्यता का समय लगभग 4000 ई.पू. माना जाता है। मोहनजोदड़ो का क्षेत्र करीब 300 हेक्टेयर है, जबकि राखीगढ़ी 550 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में फैला है।
- प्रो. शिंदे के अनुसार प्राचीन सभ्यता के साक्ष्यों को सँजोए राखीगढ़ी में मिले प्रमाण इस ओर भी इशारा करते हैं कि व्यापारिक लेन-देन के मामले में भी यह स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ज़्यादा समृद्ध था।
- अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, गुजरात और राजस्थान से इसका व्यापारिक संबंध था। खासतौर पर आभूषण बनाने के लिये लोग यहाँ से कच्चा माल लाते थे, फिर इनके आभूषण बनाकर इन्हीं जगहों में बेचते थे। इस सभ्यता के लोग तांबा, कार्नेलियन, अगेट, सोने जैसी मूल्यवान धातुओं को पिघलाकर इनसे नक्शीदार मनके की माला बनाते थे। पत्थरों या धातुओं से जेवर बनाने के लिये भट्टियों का इस्तेमाल होता था। इस तरह की भट्टियाँ भारी मात्रा में मिली हैं। यहाँ मिले कंकालों का डीएनए परीक्षण चल रहा है।

हरियाणा में शुरू होगी 'ई-बुक्स योजना', 'सुषमा स्वराज स्मृति सम्मान' भी होगी शुरू

चर्चा में क्यों ?

13 सितंबर, 2022 को हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. चंद्र त्रिखा ने बताया कि हरियाणा में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये इस साल के अंत तक 'ई-बुक्स योजना' शुरू होगी। अकादमी पहले चरण में पाँच सुप्रसिद्ध पुस्तकों की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करवा रही है।

प्रमुख बिंदु

- निदेशक डॉ. चंद्र त्रिखा ने बताया कि सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद की 'गोदान', रामधारी सिहं दिनकर की 'रश्मि थी', 'कुरुक्षेत्र', धर्मवीर भारती की 'कनुप्रिया'और 'अंधा युग' की ई-बुक्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। इनके साथ ही कुछ पौराणिक ग्रंथों की रिकॉर्डिंग का काम भी चल रहा है।
- नए रचनाकारों के प्रोत्साहन के लिये ज़िला स्तर पर लेखन कार्यशालाएँ प्रस्तावित हैं। भाषण कला एवं हिन्दी में विशेष लेखन को प्रोत्साहित करने के लिये 'सुषमा स्वराज स्मृति सम्मान' शुरू किया जा रहा हैं। इसमें लेखकों को पाँच लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा।
- उन्होंने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा के हिन्दी साहित्य पर पुस्तकें तैयार की जा रहीं हैं। बीते वर्ष अकादमी का यूट्यूब चैनल शुरू किया गया था, जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बीते एक वर्ष के दौरान चार नई योजनाएँ भी शुरू की गई हैं। साहित्यकार सम्मान योजना, श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, हरिगंधा पुस्तिका का प्रकाशन और साहित्यिक आयोजन इनमें शामिल हैं।

नोट :

अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं और सामाजिक क्षेत्र के संस्थानों को सौर ऊर्जा पर मिलेगी क्रमश: 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत सब्सिडी

चर्चा में क्यों ?

14 सितंबर, 2022 को हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में बढ़ावा देने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने हरियाणा में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं की छतों पर लगाए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों पर 75 प्रतिशत सब्सिडी और सामाजिक संस्थानों के भवनों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- चौधरी रणजीत सिंह ने यह जानकारी अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थानों के भवनों पर राज्य सरकार 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता देगी और शेष 50 प्रतिशत खर्च लाभार्थी संस्थानों को वहन करना होगा।
- बिजली मंत्री ने कहा कि 'म्हारा गाँव, जगमग गाँव'योजना के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। बिजली विभाग भी बिजली चोरी रोकने के लिये निरंतर अभियान चला रहा है।
- उन्होंने बताया की वर्ष 2019-20 में 171688 परिसरों में चेकिंग की गई और 45394 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए तथा79 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 92.94 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई।
- इसी प्रकार 2020-21 में 226213 परिसरों में चेकिंग की गई और 73524 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए तथा71 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 131.7 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई
- वर्ष 2021-22 में 312102 परिसरों में चेकिंग की गई और 75839 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए तथा 272.23 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 132.53 करोड़ रुपए की राशि वसूली गई। इस प्रकार कुल 357.17 करोड़ रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई।

फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का विश्वस्तरीय स्टेशन की तर्ज़ पर होगा पुनर्विकास

चर्चा में क्यों ?

15 सितंबर, 2022 को केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की महत्त्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने हेतु चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि पुनर्विकास कार्यों के द्वारा इस रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिये प्रमुख उन्नयन कार्य किये जाएंगे।
- इस परियोजना की कुल राशि 262 करोड़ रुपए है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत फरीदाबाद स्टेशन पर दोनों ओर आईकॉनिक भवन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह आगमन व प्रस्थान की अलग-अलग सुविधा होंगी।
- स्टेशन के दोनों ओर मल्टी लेवल कार पार्किंग होगी। 72 मीटर चौड़ा सुसज्जित स्थान रेलवे स्टेशन के दोनों ओर होगा। 12 मीटर चौड़े दो फुट-ओवर-ब्रिज भी यहाँ बनाए जाएंगे, ताकि बाधारहित आवागमन किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त अधिक क्षमता व स्थान युक्त प्रतीक्षालय क्षेत्र, फूड कोर्ट सहित अन्य सुविधाएँ भी यहाँ विकसित की जाएंगी।
- नए प्रस्ताव में रेलवे स्टेशन परिसर में ही स्थानीय परिवहन हेतु सुविधा का भी प्रावधान है। इसके साथ-साथ रेलवे स्टेशन के भवन को स्मार्ट तथा हरित भवन की तर्ज़ पर पुनर्विकसित किया जाएगा।

नोट :

एचएयू के कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

14 सितंबर, 2022 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में आयोजित आउटलुक शिखर सम्मेलन और स्वराज पुरस्कार-2022 कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र, महेंद्रगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र के पुरस्कार से नवाजा।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.आर. काम्बोज को यह पुरस्कार प्रदान किया।
- उल्लेखनीय है कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिये कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी 11 कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थानों से 731 कृषि विज्ञान केंद्रों ने आवेदन किया था, जिनमें से पुरस्कार के लिये उक्त केंद्र को चुना गया।
- कृषि विज्ञान केंद्र, महेंद्रगढ़ को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नवीन प्रौद्योगिकियों का खेत प्रदर्शनों के माध्यम से व्यापक प्रसार, कृषि में युवाओं को आकर्षित करना (आर्या) परियोजना के अंतर्गत उद्यम इकाईयों की स्थापना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अंतर्गत मौसम की सटीक जानकारी किसानों तक सही समय पर पहुँचाने, कृषि में कार्यरत् महिलाओं में पोषक तत्त्वों के प्रति संवेदनशील कृषि संसाधन और नवाचार के साथ-साथ विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से अनुसूचित जाति के युवाओं के स्वरोज़गार, भूमि सुधार के लिये मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर खादों का संतुलित मात्रा में प्रयोग व सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिये संचालित विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वन के दृष्टिगत प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सफल बनाने में हरियाणा की नई पहल

चर्चा में क्यों ?

19 सितंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' को सफल बनाने हेतु मत्स्य पालक किसानों के लिये एक नई पहल की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने नई पहल के रूप में बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार से आने वाली जो सब्सिडी देर से आती है, वह सब्सिडी अब हरियाणा सरकार एडवांस में देगी।
- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने सिरसा ज़िले के मछली पालकों के लिये सिरसा में ही मछलीपालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की, जिससे यहाँ के झींगा मछली पालकों को सीधे लाभ होगा। इससे पहले यहाँ के मछली पालकों को रोहतक जाकर लैब टेस्टिंग की सुविधा लेनी पड़ती थी।
- इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मछली की खरीद व बिक्री के लिये झज्जर या गुरुग्राम में से किसी एक ज़िले में थोक मछली मार्केट स्थापित करने की भी घोषणा की, जिससे किसानों को आर्थिक तरक्की में लाभ मिलेगा।
- मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भिवानी ज़िले के गरवा गाँव में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक्वापार्क बनाया जाएगा। यह एक्वापार्क 25 एकड़ में होगा। इसमें मछली पालन से जुड़े नए-नए शोध, मछली पालन की नई किस्म, बीज पर शोध किया जाएगा। इससे मछली पालकों को सीधे लाभ मिलेगा।

हरियाणा एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी-2022 का प्रारूप तैयार

चर्चा में क्यों ?

19 सितंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में राज्य में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर पूर्णरूप से रोक लगाने तथा पराली का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा हरियाणा एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी-2022 का प्रारूप तैयार किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी-2022 के प्रारूप को अंतिम मंज़ूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदान की जाएगी।
- मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी-2022 का उद्देश्य पराली आधारित बायोमास, बिजली परियोजनाओं, उद्योगों, कम्प्रैस्ड बायोगैस संयंत्रों, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों, ईंट-भट्ठों, पैकेजिंग सामग्री इत्यादि में निवेश को आकर्षित करने के लिये अनुकूल वातावरण बनाना है। इसके साथ ही किसानों को अपने खेत में पराली को काटने, गठरी बनाने और स्टोर करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा विभिन्न परियोजनाओं में उपयोग के लिये इसे बेचने की सुविधा प्रदान करना है।
- इस नीति के माध्यम से फसल के अवशेषों की मांग और आपूर्ति प्रबंधन के लिये किसानों व उद्योगों/गोशालाओं/उपयोगकर्त्ताओं के बीच लिंक स्थापित किया जाएगा। साथ ही, विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों, ईंट-भट्ठों या किसी अन्य औद्योगिक, वाणिज्यिक या संस्थागत प्रतिष्ठानों में पराली का उपयोग करने पर भी ज़ोर दिया जाएगा।
- नई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देना भी इस नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक है।
- राज्य में पावर प्रोजेक्ट्स, सीबीजी प्लांट, एथनॉल और अन्य बायोफ्यूल के उपयोग को प्रचलित करने के लिये इस नीति के प्रारूप में विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया गया है।
- मुख्य सचिव ने कहा कि पराली की मांग के लिये ज़िलावार मैपिंग करने की रणनीति को भी नीति में शामिल किया गया है।
- उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा राज्य में फसल अवशेष प्रबंधन के लिये किसानों को जागरूक व प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी के तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर तथा कस्टमर हायरिंग सेंटर खोलने के लिये 80 प्रतिशत सब्सिडी पर बेलिंग यूनिट (हे-रेक, शर्ब मास्टर और स्ट्रॉ बेलर) उपलब्ध करवाई जा रही है।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को मिला आईडीए एजुकेशन अवार्ड-2022

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए आईडीए एजुकेशन अवार्ड 2022 प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- विश्वविद्यालय को यह अवार्ड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों के लिये किये गए कार्यों हेतु प्रदान किया गया है।
- इंडिया डेडिकेट्स एसोसिएशन (आईडीए) द्वारा बंगलूरू में आयोजित एक कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की ओर से यह अवार्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने ग्रहण किया।
- विदित है कि आईडीए अवार्ड उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित अवार्ड है।
- आईडीए एजुकेशन अवार्ड 2022 के लिये देश के 25 राज्यों के 1100 से अधिक शिक्षण संस्थानों से 2300 से अधिक नामांकन विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त हुए थे, जिसमें उच्च शिक्षा श्रेणी के तहत हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ को यह अवार्ड स्टूडेंट एंड फैकल्टी वेलबिंग, अर्थात् संस्थान व सहभागियों के हितों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों व कर्मचारियों की शैक्षणिक व भावनात्मक ज़रूरतों एवं डिजिटल वेलनेस के लिये प्रदान किया गया है।

ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप)

चर्चा में क्यों ?

22 सितंबर, 2022 को हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव ने बताया कि एनसीआर के ज़िलों में एक अक्टूबर से ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू की जाएगी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत एनसीआर के ज़िलों में 1 अक्टूबर से जनरेटर सेट के संचालन पर प्रतिबंध होगा। केवल आवश्यक सेवाओं, जैसे- अस्पताल, मेडिकल उपकरण चलाने, सेना से संबंधित कार्यों या अन्य इमरजेंसी हालातों में ही डीजी सेट के प्रयोग की अनुमति होगी।
- साथ ही जहाँ पर पीएनजी की लाइन बिछ चुकी है वहाँ पर कोयला, डीज़ल व जनरेटर पर आधारित उद्योग नहीं चल सकेंगे। जहाँ पीएनजी की लाइन नहीं बिछ पाई है, वहाँ 1 जनवरी 2023 से यह नियम लागू होगा।
- पी. राघवेंद्र राव ने बताया कि इस बार एनसीआर में संशोधित ग्रैप लागू किया जा रहा है जिसके तहत वायु की गुणवत्ता के आधार पर ग्रैप को अलग-अलग चार स्टेज में विभाजित किया गया है। एक्यूआई अर्थात् एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर पहुँचने पर पहली स्टेज खराब की होगी। 300 से ऊपर दूसरी स्टेज ज़्यादा खराब, एक्यूआई 400 से ऊपर जाने पर स्टेज तीन गंभीर और एक्यूआई 450 से ऊपर जाने पर स्टेज चार 'वेरी सीवियर'(अति गंभीर) की होगी।
- गौरतलब है कि हरियाणा के 14 ज़िले एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। एनसीआर के ज़िलों में प्रदूषण को कम करने के लिये 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा एरिया में निर्माण व तोड़फोड़ के लिये डस्ट कंट्रोल एप पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा।
- उन्होंने बताया कि ग्रैप लागू होने पर उद्योगों में क्लीन फ्यूल के प्रयोग पर बल दिया जाएगा। जिन उद्योगों में पीएनजी गैस की सप्लाई है, वे अपने यहाँ गैस का प्रयोग करेंगे और जिन उद्योगों में गैस की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है वे बायोमास का प्रयोग फ्यूल के तौर पर करें।
- उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ढाबा, होटल और रेस्टोरेंट आदि में कोयले के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही सभी ज़िलों में एक ज़िला पर्यावरण योजना (डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट प्लान) तैयार की जाए।
- उन्होंने वायु प्रदूषण की रोकथाम में लिये विशेष मॉनिटरिंग टीमों का गठन करने और रात को पेट्रोलिंग करवाने के साथ आकस्मिक तौर पर चेकिंग करवाने की हिदायत भी दी।
- पी. राघवेंद्र राव ने बताया कि मौसम विभाग की तरह इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिरियोलॉजी वायु की गुणवत्ता के बारे में तीन दिन पहले ही पूर्व अनुमान बताएगा। पहले वायु को लेकर जानकारी उसी दिन मिलती थी, लेकिन अब लोगों को पहले से ही प्रदूषण स्तर की जानकारी मिल सकेगी। इसका लाभ यी रहेगा कि प्रदूषण से बचने के लिये लोग पहले ही तैयारी कर सकेंगे।

अंबाला से श्रीनगर और लखनऊ की हवाई यात्रा जल्द

चर्चा में क्यों ?

22 सितंबर, 2022 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नागरिक एवं उडन्यन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद अंबाला से श्रीनगर और लखनऊ के लिये हवाई सेवा जल्द ही शुरू होने की जानकारी दी है।

प्रमुख बिंदु

- अंबाला में टर्मिनल बनाने के लिये मिलिटरी के जंक्शन के साथ लगती लगभग 20 एकड़ भूमि का चयन कर लिया गया है। सेना ने यह भूमि एयरफोर्स को ट्रांसफर भी कर दी है। इस भूमि पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल बनाया जाएगा। इसके लिये केंद्रीय मंत्रालय ने सभी स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि भी मंज़ूर कर दी है।
- नागरिक एवं उडन्यन विभाग हरियाणा के अधिकारियों ने बताया कि अंबाला में हवाई यात्रा शुरू करने के लिये एयरफोर्स ने भी एनओसी दे दी है। इसके अलावा, जब तक टर्मिनल बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक अस्थायी टर्मिनल बनाकर हवाई यात्रा शुरू कर दी जाएगी।
- गृह मंत्री विज ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि हवाई यात्रा के लिये सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करें, ताकि जनता को इसका जल्दी लाभ मिल सके।

उल्लेखनीय है कि फिलहाल लोगों को हवाई सेवा के लिये चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है।

नोट :

डॉ. सोनिया खुल्लर होंगी हरियाणा की नई स्वास्थ्य महानिदेशक

चर्चा में क्यों ?

27 सितंबर, 2022 को स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव जी. अनुपमा ने डॉ. सोनिया खुल्लर को हरियाणा के स्वास्थ्य महानिदेशक के पद पर नियुक्त करने के आदेश जारी किये।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि डॉ. सोनिया त्रिखा खुल्लर हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रह चुके सीनियर आईएएस अधिकारी डॉ. राजेश खुल्लर की पत्नी हैं। ये वर्तमान में हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में जानी-मानी महिला रोग विशेषज्ञ हैं।
- वर्तमान स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. वीणा सिंह की सेवानिवृत्ति की वजह से यह पद खाली हो रहा था, अब डॉ. सोनिया खुल्लर को इस पद की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। उनके पास आहरण और संवितरण अधिकारी की शक्तियाँ भी होंगी।

हरियाणा-सस्केचेवान गोलमेज सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

28 सितंबर, 2022 को हरियाणा और कनाडा के सस्केचेवान प्रांत के बीच पारस्परिक संबंध और हितों के लिये नए अवसरों की पहचान, रणनीतिक साझेदारी, सुविधाओं, समर्थन और मज़बूती हेतु चंडीगढ़ में हरियाणा-सस्केचेवान गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा-सस्केचेवान गोलमेज सम्मेलन का आयोजन विदेश सहयोग विभाग और सस्केचेवान इंडिया कार्यालय, कनाडा उच्चायोग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
- ज्ञातव्य है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा में विदेशी निवेश को बढ़ाने हेतु राज्य सरकार ने अलग से विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है।
- राज्य का विदेश सहयोग विभाग निरंतर विदेशों से संपर्क बनाए हुए है और अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने हेतु निवेशकों के साथ बैठकें की जाती हैं। इसी कड़ी में हरियाणा-सस्केचेवान गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- इस सम्मेलन में विदेश सहयोग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव योगेंद्र चौधरी ने कहा कि हरियाणा सरकार कौशल विकास, शैक्षणिक अनुसंधान, व्यापार, निर्यात और संसदीय आदान-प्रदान के क्षेत्रों में सस्केचेवान के साथ संबंधों को मज़बूत करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- उन्होंने कहा कि हरियाणा में निवेश करने की इच्छुक कनाडाई कंपनियों के साथ-साथ कनाडा में निवेश करने के इच्छुक हरियाणा के निवेशकों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- विदेश सहयोग विभाग के महानिदेशक एवं सचिव अनंत प्रकाश पांडे ने कहा कि यह सम्मेलन विदेश सहयोग विभाग, हरियाणा सरकार और कनाडा के सस्केचेवान प्रांत के व्यापार एवं निर्यात संवर्धन मंत्रालय के मध्य मार्च 2022 में हस्ताक्षरित हुए एमओआई की दिशा में बढ़ने हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- इस सम्मेलन ने हितधारकों को उक्त समझौते के तहत रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने के लिये एक साथ लाने हेतु एक उपयुक्त मंच प्रदान किया है।
- भारत में कैनेडियन मिशन की असिस्टेंट डिप्टी मिनिस्टर रिचेल ने कहा कि सस्केचेवान और हरियाणा की विकास यात्रा में बहुत समानताएँ हैं। दोनों प्रांतों में विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास के सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिये एक-दूसरे के सामर्थ्य का लाभ उठाने की अपार संभावनाएँ हैं।

नोट :

अंबाला ज़िले के बड़ौला में स्थित सरकारी स्कूल का नाम होगा शहीद करनैल सिंह या उनकी पत्नी के नाम पर

चर्चा में क्यों ?

28 सितंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के अंबाला ज़िले के बड़ौला गाँव में स्थित मिडिल स्कूल का नाम शहीद करनैल सिंह बेनिपाल या उनकी पत्नी चरणजीत कौर के नाम पर रखने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि गोवा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जाने वाली सड़क का नाम गोवा की आज़ादी के लिये अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हरियाणा के शहीद करनैल सिंह बेनिपाल के नाम पर रखा जाएगा।
- मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत शहीद करनैल सिंह बेनिपाल की पत्नी श्रीमती चरणजीत कौर से अंबाला ज़िले के बड़ौला गाँव में मिले तथा उन्हें गोवा सरकार की तरफ से प्रशस्ति-पत्र और 10 लाख रुपए का चेक दिया।
- डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा की आज़ादी के लिये शहादत देने वाले ज्ञात और अज्ञात शहीदों की याद में गोवा के पतरादेवी में शहीदों की याद में मेमोरियल बनाया जा रहा है। पतरादेवी के सरकारी स्कूल में शहीद करनैल सिंह बेनिपाल का स्टैच्यू भी बनाया गया है।
- अंबाला के विधायक असीम गोयल ने कहा की बड़ौला पंचायत दोनों में से जिसके नाम का प्रस्ताव पास करेगी, उसी के नाम पर स्कूल का नाम रखा जाएगा।

चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम हुआ शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

चर्चा में क्यों ?

28 सितंबर, 2022 को स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती के अवसर पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़ हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस नाम का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि मोहाली-चंडीगढ़ के नाम पर राजनीति के चलते 14 वर्षों से चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर नहीं हो सका था। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की सरकारें एयरपोर्ट का नाम सरदार भगत सिंह के नाम पर रखे जाने पर तो सहमत थीं, लेकिन पंजाब सरकार इसके पीछे मोहाली लगाना चाहती थी और हरियाणा सरकार चंडीगढ़ को नहीं बदलना चाहती थी।
- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखे जाने की घोषणा की थी।
- विदित है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया (एएआई), पंजाब और हरियाणा सरकार का संयुक्त उद्यम हैं। इस परियोजना में एएआई की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि पंजाब एवं हरियाणा सरकार की 5 और 24.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर, 2015 को किया था।
- वर्तमान समय में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 82 फ्लाइट का संचालन हो रहा है। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, श्रीनगर, अहमदाबाद, गोवा, बंगलुरु, हैदराबाद, कुल्लू, पुणे, लेह, लखनऊ, कोलकाता, हिसार, देहरादून के लिये इस एयरपोर्ट से सीधी फ्लाइट है। जबकि इस हवाई अड्डे से केवल दो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें-दुबई और शारजाह के लिये ही उपलब्ध हैं।

नोट :

गुरुग्राम और नूंह में स्थापित होगा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क

चर्चा में क्यों ?

29 सितंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि राज्य के गुरुग्राम और नूंह ज़िलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10 हज़ार एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- यह परियोजना दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह में है, जो फरवरी 2022 में खोला गया था, जिसका क्षेत्रफल करीब दो हज़ार एकड़ है।
- प्रस्तावित अरावली पार्क आकार का 5 गुना होगा और इसमें एक बड़ा हर्पेटेरियम, एवियरी/बर्ड पार्क, बिग कैट्स के चार ज़ोन, शाकाहारी जानवरों के लिये एक बड़ा क्षेत्र, विदेशी पशु-पक्षियों के लिये एक क्षेत्र, एक अंडरवाटर वर्ल्ड, नेचर ट्रेल्स/विजिटर/टूरिज्म ज़ोन, बॉटेनिकल गार्डन/बायोमेस, इक्वाटोरियल/ट्रॉपिकल/कोस्टल/डेजर्ट इत्यादि होंगे।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा-एनसीआर क्षेत्र में जंगल सफारी की अपार संभावनाएँ हैं। जंगल सफारी योजना के साकार होने के बाद एनसीआर में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
- हरियाणा की जंगल सफारी परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और हरियाणा सरकार की एक संयुक्त परियोजना होगी। एक योजना के तहत केंद्र सरकार भी हरियाणा को इस परियोजना के लिये फंड मुहैया कराएगी।
- परियोजना के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय ईओआई मंगाई गई थी और ऐसी सुविधाओं की डिज़ाइन व संचालन में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाली दो कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। वे अब पार्क की डिज़ाइन, निर्माण की निगरानी और संचालन के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन प्रतियोगिता में भाग लेंगी। वहीं एक अरावली फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, जो परियोजना का प्रबंधन करेगा।
- सीएम ने कहा कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसके लिये क्षेत्र का मूल्यांकन अध्ययन किया और इस तरह के पार्क की स्थापना की तकनीकी व्यवहार्यता से सहमत हो गया है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि जंगल सफारी विकसित होने से एक ओर जहाँ इस पर्वत श्रृंखला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों से यहाँ काफी संख्या में लोग पर्यटन के लिये आएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। आसपास के गाँवों में ग्रामीणों को होम स्टे पॉलिसी के तहत लाभ होगा।
- गौरतलब है कि अरावली पर्वत श्रृंखला एक सांस्कृतिक धरोहर है, जहाँ पर पक्षियों, वन्य प्राणियों, तितलियों आदि की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कुछ वर्षों पहले करवाए गए सर्वे के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला में पक्षियों की 180 प्रजातियाँ, मैमल्स, अर्थात् स्तनधारी वन्य जीवों की 15 प्रजातियाँ, रेप्टाइल्स अर्थात् ज़मीन पर रेंगने वाले और पानी में रहने वाले प्राणियों की 29 प्रजातियाँ तथा तितलियों की 57 प्रजातियाँ विद्यमान हैं।

हरियाणा राज्य में पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्डचेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ

चर्चा में क्यों ?

29 सितंबर,2022 को बर्मिंघम (यूके) में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे. पी. दलाल की उपस्थिति में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने हरियाणा सरकार की ओर से बर्मिंघम विश्वविद्यालय के साथ हरियाणा राज्य में पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं कोल्डचेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि कृषि मंत्री और अन्य अधिकारी 29 व 30 सितंबर को बर्मिंघम विश्वविद्यालय में चल रही कोल्ड चेन समिट में भाग लेने बर्मिंघम गए हैं तथा हरियाणा में स्थापित होने वाले उत्कृष्टता केंद्र से जुड़े वहाँ के संस्थानों का दौरा भी करेंगे।

नोट :

- मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि यह उत्कृष्टता केंद्र फसल तुड़ाई उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने, किसानों व अन्य हितधारकों का ज्ञानवर्धन करने, पर्यावरण व किसानों के अनुकूल तकनीकों के इस्तेमाल तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इसके फलस्वरूप राज्य में बागवानी की ओर विविधीकरण में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी।
- कोल्डचेन समिट में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा ने वर्तमान में कुल फसली क्षेत्र का लगभग 7 प्रतिशत क्षेत्र बागवानी फसलों के अंतर्गत है। राज्य में 393 बागवानी क्लस्टर, 13 एकीकृत पैकहाउस बनाए जा चुके हैं व 50 अन्य पैक हाउस निर्माणाधीन हैं। आने वाले पाँच सालों में 500 और एकीकृत पैक हाउस स्थापित किये जाएंगे।
- उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य ताजा फलों एवं सब्जियों की व्यवस्थित सप्लाई चेन व किसानों को सीधा कृषि बाज़ार से जोड़ने में एक अग्राणी राज्य होगा। राज्य में अब तक कृषि क्षेत्र की कंपनियों के साथ विभिन्न किसान समूह संगठनों द्वारा 59 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।
- उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन को मज़बूत करने के लिये एकीकृत पैकहाउस स्थापित करने, प्री-शिपमेंट ट्रीटमेंट सुविधाएँ, जैसे- ई-रेडिऐशन, वाष्प हीट ट्रीटमेंट (वी.एच.टी), हॉट वाटर डिप ट्रीटमेंट (एच.डब्ल्यू.डी.टी) आदि सृजित करने की आवश्यकता है।
- डॉ. सुमिता मिश्रा ने स्वच्छ हरित ऊर्जा तथा कोल्ड चेन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिये एक अनुकूल प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात की, ताकि फसलों की तुड़ाई से लेकर खुदरा ब्रिकी तक होने वाले नुकसान को रोका जा सके।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर किसानों के हित में कल्याणकारी योजनाएँ चला रही है। हरियाणा ने एक नई पहल शुरू करते हुए बागवानी किसानों को जोखिममुक्त करने के लिये भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई है।
- इसके अलावा, राज्य सरकार निरंतर बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिये फसल विविधीकरण को अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित कर रही है।

The Vision

नोट :